भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी की फसल को हानि का अनुमान

*214. **श्री जी० एस० तोहरा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को हाल में पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के कई क्षेत्रों में बेमौसम वर्षा होने से रबी की फसलों को हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निगम की रिपोर्ट क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं । ऐसा अनुमान सामान्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कटिहार में तटबन्ध का निर्माण

*215. **श्री युवराज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये लगभग 150 किलोमीटर लम्बे तटबंध का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या इस तटबंध के पूरा हो जाने से लाखों एकड़ फसल की रक्षा होगी और सदियों से हो रही क्षति से जनसाधारण की रक्षा हो सकेगी ;

(ग) क्या बिहार की सीमा पर पश्चिम बंगाल के मालदह जिले में इसके मुकाबले का तटबंध बनाया गया है ;

(घ) क्या तटबंध की सुरक्षा के लिये सर्विस-रोड का निर्माण आवश्यक है ताकि तटबंध को मजबूत बनाया जा सके और उस पर निगरानी रखी जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का बंगाल की तरह बिहार राज्य के तटबंध पर सर्विस-रोड बनाने और 'ब्लैक-टोप्पिंग' की व्यवस्था करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). महानन्दा नदी की फूलहार और बरसोई शाखाओं की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की रक्षा के लिए बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में समन्वित स्कीमें तैयार की थीं । बिहार की स्कीम में अन्य बातों के अलावा पूर्णिया और कटिहार जिलों में 249 किलोमीटर लंबे तटबंधों का निर्माण और पश्चिम बंगाल की स्कीम में फूलहार के वामतट पर 39.5 किलोमीटर तथा बरसोई के दक्षिण तट पर 48 किलोमीटर लंबे तटबंधों का निर्माण करना परिकल्पित था । आशा है कि इन स्कीमों से बिहार में लगभग एक लाख हैक्टेयर तथा पश्चिम बंगाल में 81,920 हैक्टेयर क्षेत्र को नदी के पानी के फैलाव एवं बाढ़ द्वारा जलमग्न होने से सुरक्षा प्राप्त होगी और इसके परिणामस्वरूप फसलों को क्षति नहीं पहुंचेगी ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने बिहार द्वारा निर्मित तटबंध के साथ-साथ फूलहार ब्रांच के वामतट पर तथा बिहार में दूसरे किनारे पर बने तटबंध के सामने मालदा जिले में अपनी सीमा में तटबंध बनाया है ।

(घ) और (ङ). सामान्यत : सभी बृह दे तटबंधों पर कच्ची सड़कों की व्यवस्था की जाती है परन्तु तटबंधों पर पक्की सड़कों

के निर्माण के लिए कोई पक्के नियम नहीं बनाए जा सकते । इसमें संदेह नहीं कि इनकी व्यवस्था करना वांछनीय है, परन्तु ऐसा होना बहुत सी बातों पर निर्भर होता है । जिनमें सड़कों के वर्तमान नैट-वर्क से तटबंधों की दूरी, भूतल पर जमीन की किस्म, सुरक्षित क्षत्र की महत्ता और इस उद्देश्य के लिए संसाधनों की उपलब्धता, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, आदि बातें शामिल हैं । चूंकि इस कार्य पर बहुत अधिक राशि व्यय होती है इसलिए अब तक तटबंधों पर पक्की सड़कों के निर्माण की प्रैक्टिस नहीं रही है यद्यपि सामान्यत: तटबंधों को इतना चौड़ा बनाया जाता है कि वे निरीक्षण एवं सर्विस सड़कों का काम दे सकें, जिन पर गाड़ियों का यातायात हो सके । बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि तटबंधों का ऊपरी मार्ग स्वयं ही सर्विस-रोड का काम देता है इस लिए तटबंधों पर पक्की सड़कों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है । महानन्दा तटबंध की ऊपरी सतह 4.8 मीटर से 7.6 मीटर तक चौड़ी है जो सर्विस-रोड के वास्ते पर्याप्त है । फिलहाल का तटबंध पर ब्लैक-टोपिंग सहित नियमित सड़क के निर्माण का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

Subsidy for tube-wells and bore-wells

*216. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government have included bore-wells and tube-wells also under minor irrigation;

(b) if so, whether the Government are giving subsidy for these wells as in the case of digging open wells; and

(c) the amount set apart for this during this year?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir; both wells and tube-wells form important items of the Minor irrigation Programme.

(b) Subsidies are made available for wells and tube-wells (including pump-sets) in the States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Tripura, U.P. and West Bengal from the State Plan provisions. In addition subsidies are also available for these works from the Central sector programmes such as Small Farmers Development Agencies, Drought Prone Areas Programme, Integrated Tribal Development Programme and Command Area Development Programme.

(c) The total amount of subsidy expected to be available from the State Plan provisions for wells (including tube-wells and pump-sets) during the current year is estimated as Rs. 2.00 crores. In addition an amount of Rs. 45 crores is expected to be released under the Small Farmers Development Agencies. This will include about 30 to 40 per cent of the total amount as subsidy for wells (including pump-sets). Besides some subsidies will also be available from the Central sector programmes of Drought Prone Areas Programme, Integrated Tribal Development Programme and Command Area Development Programme.

राजस्थान में टिड्डियों का विनाश करने के लिए चौकियां

*217. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर टिड्डियों का विनाश करने के लिये कितनी चौकियां बनी हुई हैं ; और